सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) "अखबारी कागज" उद्योग उन 59 अग्रता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल हैं जिन्हे पुर्जे, अनुरक्षण सामान, आदि आयात करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। छोटे समाचार-पत्रो के इस्तेमाल के लिए छपाई की छोटी मशीनें भारत में नहीं बन रही है। छपाई उद्योग 'ऋण' सुविधाओ के लिए इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन और इण्डस्ट्रीज क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है।

हिन्दी टेलीप्रिंटरो के बनाने का काम हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०, मद्रास द्वारा इटेलियन सप्लायर्स क्रेडिट की सहायता से शुरू किया जाएगा। भारत सरकार ने औजारो पर होने वाले और टलो के मेसर्स ओलिवती (टेलीप्रिंटर परियोजना मे सहयोगी) मे तकनीकी जानकारी प्राप्त करने पर होने वाले व्यय को वहन करना स्वीकार कर लिया है।

†[THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) and (b) The 'newsprint' industry is included in the list of 59 priority industries which are allotted priority for the import of spares, maintenance, stores etc. Small printing machines for the use of small newspapers are now being manufactured in India. The printing industry is recognised for the purpose of 'loan' facilities by the Industrial Finance Corporation and the Industries Credit and Investment Corporation of India.

The manufacture of Hindi teleprinters will be started by the Hindustan Teleprinters Ltd., Madras with the help of Italian Supplier's Credit and the Government of India have agreed to cover the cost of tooling and know-how from M/s. Olivetti of Italy (collaborators in the teleprinters project).]

छोटे समाचारपत्रों को सहायता

497. **श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषाओं के छोट समाचार-पत्रों को (1) ऋण की सुविधाएं (2) सीमा शुल्क से छूट, (3) सरकारी विज्ञापनों आदि के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†[ASSISTANCE TO SMALL NEWSPAPERS

497. SHRI S. K. D. PALIWAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether any steps have been taken by Government for giving assistance to the small newspapers in Indian languages in the form of (i) credit facilities, (ii) exemption from customs, (iii) Government advertisements etc.; and

(b) if so, what are the details thereof?]

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) विज्ञापन देने के मामले मे, छोटे और मंझले, विशेषकर प्रादेशिक भाषाओं के समाचार-पत्रों को अधिकतम संभव सहायता देने के लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। 1966-67 के साल में 1,134 छोटे और मंझोले समाचार पत्रो को लगभग 14.16 लाख रुपए के विज्ञापन प्राप्त हुए, जो सजावटी विज्ञापनों पर हुए कुल खर्च का 51.3 प्रतिशत था।

जहां तक वर्गीकृत विज्ञापनों का सम्बन्ध है, छोटे और मंझोले समाचार-पत्रों को ये लगभग 16 लाख रुपए के प्राप्त हुए, जो कुल खर्च का 32 प्रतिशत था। इनके लिए जो जगह

†[ ] English translation.

इस्तेमाल हुई, वह वर्गीकृत विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त कुल जगह का 62.6 प्रतिशत थी। परिवार आयोजन, पंचवर्षीय योजनाओं, बचत और खाद्य जैसे शिक्षा प्राप्त और जानकारी देने वाले राष्ट्रव्यापी अभियानों के बारे में सरकारी विज्ञापन मुख्यत: छोटे समाचार-पत्रों को ही दिए जाते हैं। छोटे समाचार-पत्रों को बड़े विज्ञापन देने के भी प्रयत्न किए जाते हैं।

छोट समाचार-पत्रों सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार छोटे समाचार-पत्रों को ऋण की सुविधाएं देने और एक समाचार-पत्र वित्त निगम स्थापित करने का सवाल सरकार के विचाराधीन है।

अखबारी कागज पर उत्पादन शुल्क एवं 50 रुपए प्रति मीटरी टन का प्रतिप्रभावी शुल्क हटाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इससे छोटे समाचार-पत्रों को लाभ होगा।

†[THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) and (b) Continuous efforts are being made by the Government to extend the maximum possible assistance to small and medium newspapers especially in regional languages in the matter of issue of advertisements. During the year 1966-67, 1134 small and medium papers received advertisements worth about Rs. 14.16 lakhs, *i.e.*, 51:3 per cent. of the total allotment on display advertisements.

As regards classified advertisements, this category of papers received about Rs. 16 lakhs, *i.e.*, 32 per cent. of the total expenditure which in terms of space came to 62.6 per cent. of the total space used on this account. In the case of national motivation campaigns of an educative and informative character like Family Planning, Five Year Plans, Savings and Food, Government advertisements are mainly channelised through small papers. Efforts are also made to give larger advertisements to smaller newspapers.

The question extending credit facilities to small newspapers and setting up a Newspaper Finance Corporation as per the recommendations of the Enquiry Committee on Small Newspapers is under consideration of Government.

The proposal to abolish the excise duty as well as countervailing duty of Rs. 50 per metric tonne on newsprint is under consideration. It will benefit small newspapers.]

†[ ] English translation.

KASHMIR IN U. N.

498. SHRI SITARAM JAIPURIA:
SHRI NARINDAR SINGH BRAR:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it has come to the notice of Government that Pakistan is proposing to raise the Kashmir question in the Security Council in the near future;

(b) if so, what is Government's reaction in this matter; and

(c) whether the Soviet authorities have been sounded about the violation of Tashkent Declaration by raising the Kashmir question again and again in the United Nations?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI M. C. CHAGLA): (a) Government have seen press reports to this effect.

(b) Government's position on the Kashmir question has been made clear, time and again, in Parliament and in the Security Council. If the question is raised in the Security Council, Government will deal with the situation suitably.

(c) No. Sir, Government do not consider this necessary.